अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से आर्थिक नियोजन के प्रकार का वर्गीकरण निम्न आधारों पर कर सकता है—

1. भौतिक नियोजन व वित्तीय नियोजन
2. आज्ञामूलक नियोजन व प्रोत्साहनमूलक नियोजन
3. केन्द्रित और विकेन्द्रित नियोजन
4. ऊपर से नियोजन एवं नीचे से नियोजन
5. पूँजीवादी, साम्यवादी, समाजवादी, तानाशाही, प्रजातांत्रिक व गाँधीवादी नियोजन
6. क्रियात्मक एवं संरचनात्मक नियोजन
7. सामान्य एवं आंशिक नियोजन
8. क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय नियोजन
9. सांकेतिक नियोजन

1. भौतिक नियोजन व वित्तीय नियोजन (Physical Planning and Financial Planning)

(i) **भौतिक नियोजन** (Physical Planning)—यह नियोजन की वह पद्धति है जिसमें योजना की आवश्यकताओं तथा लक्ष्यों को वास्तविक वस्तुओं और सेवाओं के रूप में व्यक्त किया जाता है।

(ii) **वित्तीय नियोजन** (Financial Planning)—वित्तीय नियोजन आर्थिक योजनाओं की आवश्यकताओं तथा लक्ष्यों आदि को मुद्रा के रूप में व्यक्त करता है।

नियोजन के किस स्वरूप को प्राथमिकता दी जाये? वास्तव में, भौतिक एवं वित्तीय नियोजन एक-दूसरे के प्रतिस्पर्द्धी न होकर पूरक हैं और दोनों का ही उद्देश्य अर्थव्यवस्था को उच्च संतुलन स्तर पर बनाये रखना है। वित्तीय साधनों को ध्यान में रखकर ही नियोजन के भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं और भौतिक लक्ष्य के अनुसार ही साधन अर्थात् मुद्रा की व्यवस्था की जाती है।

2. आज्ञामूलक नियोजन व प्रोत्साहनमूलक नियोजन (Planning by Direction and Planning by Inducement)

(i) **आज्ञामूलक नियोजन** (Planning by Direction)—आज्ञामूलक नियोजन के अंतर्गत नियोजन सत्ता कुछ उद्देश्यों को सुनिश्चित करके जनता को कुछ विशिष्ट रीतियों के अनुसार ही कार्य करने की अनुमति देती है तथा साथ ही कुछ अन्य विशिष्ट प्रकार के कार्य करने पर रोक लगा देती है।

(ii) **प्रोत्साहनमूलक नियोजन** (Planning by Inducement)—प्रोत्साहनमूलक नियोजन में नियोजन सत्ता प्रशुल्क एवं वित्तीय नीतियों एवं मूल्य नियंत्रण के द्वारा जनता को ऐसी आर्थिक क्रियाएँ सम्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करती है जिनसे देश का आर्थिक विकास संभव होता है।

भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं में आज्ञामूलक तथा प्रोत्साहनमूलक दोनों प्रकार के नियोजन की उपस्थिति देखने को मिलती है। वैसे अधिकांश जनमत प्रोत्साहनमूलक नियोजन का समर्थक है।

3. केन्द्रित और विकेन्द्रित नियोजन (Centralised and Decentralised Planning)

(i) **केन्द्रित नियोजन** (Centralised Planning)—केन्द्रित नियोजन उस नियोजन को कहते हैं जिसमें समस्त आर्थिक निर्णय केन्द्रीय सत्ता द्वारा ही लिये जाते हैं तथा संचालन निम्नस्तरीय बिन्दुओं द्वारा किया जाता है। केन्द्रित नियोजन **साम्यवादी देशों** में पाया जाता है।

(ii) **विकेन्द्रित नियोजन** (Decentralised Planning)—इस नियोजन में कुछ ही निर्णय केन्द्रीय सत्ता लेती है, शेष समस्त निर्णय लेने का अधिकार निम्नस्तरीय बिन्दुओं का होता है। यह व्यवस्था **प्रजातांत्रिक देशों** में पायी जाती है।

4. ऊपर से नियोजन एवं नीचे से नियोजन (Planning from Above and Planning from Below)

(i) **ऊपर से नियोजन** (Planning from Above)—ऊपर से नियोजन का अर्थ है देश के असंगठित एवं अर्द्धसंगठित क्षेत्रों का और अधिक विकास करने के लिए नियोजन करना। जब योजना का निर्माण व स्वरूप इस प्रकार का हो कि उससे उत्पन्न वर्ग को अधिक लाभ पहुँचता हो तो उसे ऊपर से नियोजन कहते हैं।

(ii) **नीचे से नियोजन** (Planning from Below)—नीचे से नियोजन का अभिप्राय, सर्वप्रथम निम्न वर्ग तथा अविकसित क्षेत्र के लिए नियोजन करना होता है। इस प्रकार के नियोजन में योजना का स्वरूप इस प्रकार का होता है कि उसका लाभ समाज के निर्धन वर्ग को अधिक प्राप्त हो सके।

भारतीय नियोजन में यद्यपि नियोजन के इन दोनों स्वरूपों को स्थान दिया गया है परंतु योजनाओं की अधिकांश रूपरेखा 'ऊपर से नियोजन' के सिद्धान्त पर आधारित रही है।

5. पूँजीवादी, साम्यवादी, समाजवादी, तानाशाही, प्रजातांत्रिक व गाँधीवादी नियोजन (Capitalist, Communist, Socialistic, Fascist, Democratic, Ghandhian Planning)

(i) **पूँजीवादी नियोजन** (Capitalist Planning)—पूँजीवादी आर्थिक संगठन की वह प्रणाली है, जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर व्यक्तिगत लोगों का अधिकार होता है। स्वतन्त्र प्रतियोगिता के बीच सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाएँ सम्पन्न की जाती हैं तथा राजकीय हस्तक्षेप को उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है।

(ii) **साम्यवादी नियोजन** (Communist Planning)—साम्यवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो आर्थिक नियोजन किया जाता है, उसे साम्यवादी नियोजन कहते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था के सभी कार्यों का संचालन राजकीय नियंत्रण एवं निर्देशन में किया जाता है। इस प्रकार के नियोजन में सभी क्षेत्र, जैसे—उत्पादन, वितरण, उपभोग आदि पर सरकार का ही अधिकार होता है।

(iii) **समाजवादी नियोजन** (Socialistic Planning)—समाजवादी नियोजन से अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जिसमें उत्पादन के भौतिक साधन किसी सार्वजनिक शक्ति या ऐच्छिक संघ द्वारा संचालित एवं नियंत्रित किये जाते हैं। इसमें निजी क्षेत्र को सीमित कर दिया जाता है तथा उत्पादन साधनों पर समाज व सरकार का नियंत्रण रहता है। आधारभूत उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में होते हैं तथा नियोजन केन्द्रीय होता है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विषमताओं को दूर करना है।

(iv) **तानाशाही या अधिनायकवादी नियोजन** (Fascist Planning)—तानाशाही नियोजन के अंतर्गत संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का संचालन केन्द्रीय शक्ति या तानाशाह के द्वारा संपन्न किया जाता है। इसमें उत्पादन के साधन निजी अधिकार में होते हैं तथा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक शक्ति का संकेन्द्रीकरण प्रशासकीय अंकुशों द्वारा रोका जाता है।

(v) **प्रजातांत्रिक नियोजन** (Democratic Planning)—इस प्रकार का नियोजन प्राय: मिश्रित अर्थव्यवस्था में अपनाया जाता है। यह समाजवादी एवं पूँजीवादी नियोजन का सम्मिश्रण होता है क्योंकि इसमें समाजवादी नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति प्रजातांत्रिक ढंग से की जाती है। इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था में नियोजन भी कहते हैं।

(vi) **गाँधीवादी नियोजन** (Gandhian Planning)—नियोजन के इस रूप का जन्म भारत में गाँधीजी के विचारों के आधार पर हुआ है। इस नियोजन को 'सर्वोदयी नियोजन' भी कहते हैं। गाँधीवादी नियोजन में सभी क्षेत्रों में पर्याप्त विकास तथा उद्योगों के विकेन्द्रीकरण पर जोर दिया गया है अर्थात् सर्वांगीण विकास की बात कही गयी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सर्वांगीण विकास करना इस नियोजन का प्राथमिक उद्देश्य है।

6. क्रियात्मक एवं संरचनात्मक नियोजन (Functional and structural planning)

यदि प्रचलित आर्थिक पद्धति के अंतर्गत ही आर्थिक विकास के लिए नियोजन किया जाता है तो उसे क्रियात्मक नियोजन कहते हैं, जबकि प्रचलित आर्थिक पद्धति में आधारभूत परिवर्तन करके नवीन व्यवस्था में नियोजन करना संरचनात्मक नियोजन कहलाता है।

यह उल्लेखनीय है कि इन दोनों स्वरूपों में अंतर होते हुए भी कोई विशेष अंतर नहीं है। संरचनात्मक नियोजन के अंतर्गत जब विकास कार्यक्रमों की पूर्ति हो जाती है तो वह स्वत: ही क्रियात्मक नियोजन का रूप ले लेता है तथा अंतत: दोनों का अंतर समाप्त होने लगता है। भारत, रूस तथा चीन के उदाहरण से यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है।

7. सामान्य एवं आंशिक नियोजन (General and partial planning)

जब कोई नियोजन संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख कर किया जाता है तो ऐसे नियोजन को सामान्य नियोजन कहते है लेकिन जब नियोजन किसी क्षेत्र के लिए किया जाता है तो ऐसा

योजन आंशिक नियोजन कहलाता है। आंशिक नियोजन को कुछ विद्वान खंडित नियोजन (Piecemeal planning) भी कहते हैं लेकिन चूँकि यह नियोजन अधूरा होता है, अत: सभी देशों में आंशिक योजन के साथ-साथ सामान्य नियोजन भी अपनाया जाता है। फलत: आंशिक नियोजन तब तक लीन होता है जब तक यह सामान्य नियोजन का रूप धारण नहीं करता है।

क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय नियोजन (Regional, National and International planning)

(i) **क्षेत्रीय नियोजन** (Regional Planning)—क्षेत्रीय नियोजन से अर्थ उस नियोजन से है एक स्वतन्त्र इकाई मानकर किसी विशेष क्षेत्र के लिए किया जाता है।

(ii) **राष्ट्रीय नियोजन** (National Planning)—राष्ट्रीय नियोजन सम्पूर्ण देश के लिए किया ता है तथा इसमें क्षेत्रीय आधार पर विभाजन करने की आवश्यकता नहीं होती।

(iii) **अंतर्राष्ट्रीय नियोजन** (International Planning)—अंतर्राष्ट्रीय नियोजन वह आर्थिक योजन है, जिसमें दो या दो से अधिक राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय सीमाओं व स्वतंत्रता के अस्तित्व को थे रखते हुए, आर्थिक विकास की प्राप्ति हेतु, परस्पर संगठित हो जाते हैं।

सांकेतिक नियोजन (Indicative Planning)

सांकेतिक नियोजन फ्रांस की मिश्रित अर्थव्यवस्था की अपनी एक विशिष्टता है। सांकेतिक योजन अन्य मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में प्रचलित नियोजन से काफी भिन्न है। जैसा कि हम जानते हैं क मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र एक साथ कार्यरत रहते हैं और निजी क्षेत्र पर ई प्रकार के नियंत्रण, जैसे—लाइसेंस, कोटा, उत्पादन का निर्धारण, कीमत में निर्धारण आदि होते , ताकि यह क्षेत्र भी सार्वजनिक क्षेत्र की भाँति सरकार के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य र सकें। इस प्रकार निजी क्षेत्र को भी सरकार के आदेशानुसार ही कार्य करना पड़ता है परंतु **सांकेतिक योजन में सरकार कोई आदेश नहीं देती है बल्कि संकेत मात्र करती है कि निजी क्षेत्र किन शाओं में योजना को कार्यान्वित करने में योगदान दे सकता है।**

भारत में नियोजन की व्यूह-रचना
(STRATEGY OF PLANNING IN INDIA)

व्यूह-रचना का अर्थ (Meaning of Strategy)—व्यूह-रचना या **'कूटनीति'** या **'विकास विधि'** से सामान्यत: अभिप्राय किसी विषय अथवा क्षेत्र-विशेष से सम्बन्धित नीतियों, पद्धतियों, सिद्धान्तों व कार्य-प्रणालियों का वह आदर्श सामंजस्य है जिसके द्वारा समस्या का सर्वोपयुक्त समाधान ढूँढने का प्रयास किया जाता है।

आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजना में नीति अपनायी जाती है, उसे योजना की व्यूह-रचना कहा जाता है। इसे विकास युक्ति (Development Strategy) या विकास कूटनीति भी कहा जाता है। इस प्रकार **व्यूह-रचना का आशय उन उपायों, नीतियों एवं प्राथमिकताओं के क्रम से है जिन्हें योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाया जाता है।**

संक्षेप में 'योजना व्यूह रचना' में तीन बातों का समावेश होता है—(i) लक्ष्य निर्धारण; (ii) प्राथमिकताओं का क्रम निर्धारण; (iii) लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपायों का चयन। व्यूह रचना में अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रतिबन्धों (Crucial Constraints) को ध्यान में ध्यान में रखते हुए स्थिरता के साथ विकास (Growth with stability) का मार्ग चुनना पड़ता है।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में व्यूह-रचना (Strategy in Different Five Year Plans)—मोटे तौर पर हमारे नियोजन की व्यूह-रचना अर्थव्यवस्था के सन्तुलित विकास पर आधारित रही है किन्तु यह उल्लेखनीय है कि आर्थिक दशाओं के बदले परिवेश में विविध क्षेत्रों में सन्तुलन बनाये रखने के लिए प्रत्येक योजना में कुछ क्षेत्रों को ऊँची प्राथमिकता देकर **असन्तुलित विकास** की कूटनीति का अनुसरण किया गया हो। मोटे तौर पर भारत के आर्थिक नियोजन की व्यूह रचना का अध्ययन हम दो शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं—

(1) 1991 तक विकास की व्यूह रचना

(2) 1991 के बाद विकास की व्यूह रचना